



आधुनिक समाचार

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

सिनेमा: ऊर्फी जावेद ने जब सिर्फ मिल्वर फॉइल लपेटकर करवाया था फोटोशैटे पोज.....

नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तापक्ष और के खिलाफ एस सी में याचिका विपक्ष दोनों तरफ से सियासी गोलबंदी दाखिल, बर्खास्त करने की मांग शुरू, जाने क्या है राजनीतिक समीकरण

नई दिल्ली। मनी लॉटिंग केस में आईएएस, आईपीएस और दूसरे को बर्खास्त करने का निर्देश देने फंसे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सरकारी नौकर को अस्थायी रूप की मांग की है। याचिका में कहा गया था कि यह विधि

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो पार्टी जैसे टीएमसी के करीबी दलों के बैठक में नहीं आने के सवाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी का नाम सुझाया। हालांकि कांग्रेस की कोशिश ही होती रही। चुनाव आयोग ने बुधवार को अधिसूचन

संक्षिप्त समाचार

वेनरल वेन सीएम
विजयन पर स्वप्ना सुरेश
ने फोड़ा एक और बम,
लगाया ये आरोप
कोच्चि। केरल में सोने की तस्करी
का मामला अभी थमा भी नहीं
था कि सीएम विजयन पर लगातार
नए आरोप लगते जा रहे हैं। मुख्य
आरोपी स्वपन सुरेश ने एक बार
फिर आरोप लगाया है कि राज्य
के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन
अपने परिवार के व्यवसायिक हित
के लिए कई लोगों से सांठगांठ
करते थे। स्वपन ने कहा कि
सितंबर 2017 में सीएम ने अपनी
बेटी के आईटी व्यवसाय खोलने
के लिए बोली को स्वीकृति देने
हेतु शारजाह के शासक से
आईकारिक दौरे के दौरान मदद
मांगी थी। स्वपन ने यह दावा
एनीकुलम जिला सत्र न्यायालय
के समक्ष दायर एक हलफनामे
में किया जो बुधवार को
सार्वजनिक हुआ।

30 को प्रयागराज में जुटेंगे तीन मंडल के किसान, उत्पादन बढ़ाने के सीखेंगे गरमीरजापुर। खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिया है। एक साथ तीन मंडल के किसानों को पैदावार बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे। इसके लिए 30 जून को प्रयागराज में मंडलीय उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रयागराज, विद्याचल व वाराणसी मंडल की सहभागिता होगी यानी तीनों मंडल वेट किसान एक साथ जुटेंगे। ज्यक्षष्टक्रूरसन्मंडलीय गोष्ठी कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में होगी। यदि उत्पादन आयुक्त उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अपर मुख्य सचिव कृषि, प्रमुख सचिव या फिर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गोष्ठी होगी। खरीफ गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक करेंगे। गोष्ठी में खरीफ अभियान से संबंधित विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। अपरिहार्य स्थिति में उनके न पहुंचने पर नामित अधिकारी को भेजा जाएगा। गोष्ठी के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त कृषि फार्म, जल जीवन मिशन स्थल आदि का भ्रमण करेंगे।

गई है। राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए गहमागहमी भी तेज हो गई है। सत्ता व विपक्ष की ओर से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बृद्धवार से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो दूसरी तरफ सत्तावधार और विपक्ष दोनों तरफ से सियासी गोलबंदी शुरू हो गई है। एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने साझा उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आम सहमति बनाने के लिए ममता बनर्जी, मिलिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, नवीन पट्टनायक और नीतीश कुमार से फोन पर बात की विपक्षी

पर ममता ने कहा कि किसी विशेष वजह से कुछ पाठियां नहीं आई हैं लेकिन इसमें संदेह नहीं कि विपक्ष एकजूट होकर राष्ट्रपति चुनाव के व अन्य दलों ने इन दोनों समेत किसी भी नाम का सुझाव नहीं दिया है। विपक्ष से राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मंथन शुरू होता उससे जारी कर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 29 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 30 कंपनियों की जांच की जाएगी। दो जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव 18 जुलाई और मतगणना 21 को होगी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का कार्यकाल 24 जुलाई तक है। सूत्रों के अनुसार पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने पर्याप्त दाखिल किया। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में जेडीयू, एआईएडीएमके, अपनन दल (सोनलाल), एलजेपी, एनपीपीए, निषाद पार्टी, एनपीएफ, एमएनएफ एआईएनआर कांग्रेस जैसे 20 छोटे दल शामिल हैं। इस तरह से एनडीए



**राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को मिल
चुके कोरोना वैक्सीन के 193.53
करोड़ से अधिक डोज़: मंत्रालय**

शिरकत का भगवर आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति से लेकर एप्पआइएम आदि ने इसमें हिस्सा नहीं खेला। राजग और संप्रग दोनों खेमों से बाहर रहने वाले दलों बीजद, वाइएसआर कांग्रेस, अकाली दल बादल ने भी बैठक से दूरी बनाई। इन दलों की राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका होनी है और ऐसे में यह विपक्ष के बाच राष्ट्रपति चुनाव में सज्जा उम्मीदवार मैदान में उतारने पर सहमति बन गई है, लेकिन प्रत्याशी अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि साक्रिय राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं राकापा प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष का सर्वसम्मत प्रत्याशी बनने से इन्कार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 17 विपक्षी दलों की बैठक में पवार के विपक्षी दलों का भा टॉलना शुरू कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की ओर से नियुक्त नेता मलिकार्जुन खड्गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, और डिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे कई दलों के नेताओं से बात की। हालांकि इस बातचीत में दोनों शामल हा भाजुडा आकड़ा के हिसाब से एनडीए को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 13 हजार वोटों की ओर जरूरत पड़ेगी। भाजपा और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48 फीसद वोट है। कांग्रेस के अगुवाई गाले यूपी के पास अर्थे दो लाख 59 हजार 892 वैल्यू वात वोट है। इनमें कांग्रेस के अलावा

**दिल्ली-एनसीआर में बारिश से लोगों को राहत,
यूपी-बिहार में आज होगी झमाझम बारिश जानें
अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम**

नई दिल्ली। भीषण गर्मी जूझ रहे दिल्लीवासियों को बारिश ने राहत दे दी है। गुरुवार देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलीं और झामाझम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा के भी कुछ इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। मौसम के अचानक करवट लेने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है और रोजाना झामाझम बरसात हो रही है। दक्षिण भारत में मानसून की वजह से बारिश हो रही है तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्री-मानसून की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। उमीद की जा रही है कि जल्द ही देशभर के सभी राज्यों में मानसून दस्तक दे देगा। आगले पांच दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को दिनभर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झाँकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 39 व 30 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। अगले चार दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भारी वर्षा होगा। पंजाब के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश होगी। उत्तराखण्ड में वर्षा से चुभती गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के साथ



राहुल से ईडी की पूछताछ को लेकर बंगलुरु में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लंबा टैफिक जाम लगाने से एंबलेंस भी फंसी

बेंगलुरु। ने शनिल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर आज एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगमेदार विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई इलाकों में सङ्कट पर उत्तरकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने ताओं ने भाजपा के खिलाफ ज्ञापन आँख शिकायत पत्र देने के लिए पार्टी वार्यालय से राजभवन तक मार्च भी निकाला। राहुल गांधी से ईडी द्वारा तीन दिन तक चली वांग्रेस संघर्षकारी विरोध कर्नाटक शिववृक्षमार ने भी सङ्कट पर उत्तरकर किया। उन्होंने कहा कि यह विरोध हमारे अधिकार है, हम न्याय वे लिए लड़े गे। इस बीच शिववृक्षमार ने आरोप लगाया कि ईडी किसी भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, वे वेवल कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर इस विरोध और मार्च से पहले बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम देखा गया जिसमें एक एंबुलेंस स र्फ़सं गई।

सम्पादकीय

कृषि उपज के कारोबार
में दूर होती बाधाएं,
बाजार तक आसान
होती किसानों की पहुंच

जिन किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने की गारंटी के लिए साल भर धरना-प्रदर्शन किया, वही आज अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को न बेचकर एमएसपी से ऊंची कीमत पर निजी कारोबारियों को बेच रहे हैं। गेहूं ही नहीं सरसों, कपास, चना की बिक्री भी समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अनाज की बिक्री के लिए पजीकरण के बावजूद किसान अपनी उपज लेकर सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी खुद उन तक जा रहे हैं। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। इस साल 29 मई तक 17.5 लाख किसानों से 184.5 लाख टन गेहूं की खरीद की गई। यह खरीद 2021-22 की सरकारी खरीद 433.4 लाख टन से 53 प्रतिशत कम है। सरकार ने 2022-23 के लिए 444 लाख टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन निजी कारोबारियों द्वारा 2,500 से 3,000 रुपये प्रति विंचल की आक्रमक खरीदारी के कारण किसान समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति विंचल की दर से गेहूं की बिक्री के लिए उत्साह नहीं दिखा रहे। जिन राज्यों में सरकारी खरीद का व्यवस्थित नेटवर्क नहीं है, वहां भी निजी एजेंसियों एमएसपी से ऊंची कीमत देकर गेहूं की खरीद कर रही है। यह भविष्य के लिए एक सुखद संकेत है। विश्व के गेहूं कारोबार में 29 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले रस-यूक्रेन के युद्धरत होने के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे विश्व में गेहूं की कीमतें बढ़ रही है। इसी कारण भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। भविष्य में गेहूं की ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद में भी बहुत से किसान उपज नहीं बेच रहे हैं। आज किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत मिल रही है तो इसका श्रेय आठ वर्षी में मोदी सरकार द्वारा किए गए विपणन सुधारों को जाता है। मोदी सरकार कृषि उपज की खरीद-बिक्री में सरकारी क्षेत्र के समानांतर निजी क्षेत्र की मौजूदगी बना रही है। इससे खरीद में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। गेहूं, सरसों, कपास के मामले में

भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी रहे नवाँन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में 10 जून को देश के विभिन्न हस्सों में जुमे की नमाज के बाद व्यापक प्रदर्शन और हिंसा देखने

जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जो उग्र प्रदर्शन हुए, उसमें भी हिंसा भड़क उठी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करना आम नागरिकों का संवैधानिक हक है, लेकिन जिस प्रकार जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और वह भी उग्र

को मिला। प्रयागराज, सहारनपुर, हावड़ा, रांची आदि शहरों में तो प्रदर्शन करने का चलन हाल के दिनों में बढ़ा है, वह न तो देश के

प्रदर्शनकारी सीधे सुरक्षा बलों से भिंग गए और आगजनी एवं पथराव कर व्यवस्था को चुनौती देने पर उत्तर आए। इन शहरों के अलावा दिल्ली स्थित शाही जामा मस्जिद से लेकर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, लुधियाना, और गंगाबाद, भद्रवाह, डोडा, किशतवाड़ आदि शहरों में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। कहीं-कहीं वे इतने उम्र थे कि या तो कफ्फूलगाना पड़ा या फिर धारा 144 लगानी पड़ी। इसके पहले 3 हित में है और न ही मुसलमानों के हित में। आखिर मुसलमान जुमे के दिन मस्जिदों से निकलकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा तो एक समय कश्मीर में होता था। क्या शेष देश का मुसलमान भी पथरबाज होने के ठप के साथ व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है मुसलमानों ने पहले ही दिन से नुपर और नवीन की टिप्पणियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। इसके बाद कई इस्लामी देशों ने भी विरोध जताया। इस पर केंद्र सरकार ने न केवल

बिहार से लेकर गुरुग्राम तक मचा बवाल
जानें इस स्कीम की उपयोगिता; एक्सपर्ट व्यू

संजय वर्मा। अग्निध योजना
[हार्डपूँच एम्पस] का एक प्रत्यक्ष लाभ
यह है कि सेना [दृष्टिर्हस्त] में आने
और वर्दी पहनकर देशसेवा की इच्छा
रखने वाले हजारों युवाओं को अपने
सपने साकार करने का मौका
मिलेगा। बेशक इनमें से दो-तिहाई
युवाओं की चार साल बाद

युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। सेना में युवाओं की अस्थायी भर्ती होगी-ऐसी चर्चा पिछले कुछ समय से निरंतर चल रही थी। अब रक्षा मंत्री ने साढ़े सत्रह साल से 21 साल के बीच के हजारों युवाओं को इस योजना में भर्ती होने और चार साल तक नौकरी करने के

योजना से तकरीबन दोगुनी अवश्य हो जाएगी। इसके अलावा अन्य फायदों पर नजर डालें तो कह सकते हैं कि सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा और वह रक्षा के लिए तय होने वाले बजट का एक बड़ा हिस्सा आगे चलकर सेना के आधिकारिकरण पर खर्च कर

केन उनके आत्मविश्वास में हुई डोटरी, अनुशासन की भावना बढ़ाने, स्वास्थ्य की जागरूकता आने और उनके नजरिये में आए फर्क काफी ज्यादा सामाजिक परिवर्तन उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है कि सेवा से बाहर आने वाला उनके हाथ में 11-12 लाख



अपने आप से सवाल करें मुसलमान,
मस्जिदों से निकलकर सड़कों पर उग्र
प्रदर्शन करके क्या संदेश देना चाहते हैं

भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी रहे नवाँन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में 10 जून को देश के विभिन्न हस्सों में जुमे की नमाज के बाद व्यापक प्रदर्शन और हिंसा देखने

जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जो उग्र प्रदर्शन हुए, उसमें भी हिंसा भड़क उठी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करना आम नागरिकों का संवैधानिक हक है, लेकिन जिस प्रकार जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और वह भी उग्र

को मिला। प्रयागराज, सहारनपुर, हावड़ा, रांची आदि शहरों में तो प्रदर्शन करने का चलन हाल के दिनों में बढ़ा है, वह न तो देश के



प्रदर्शनकारी सीधे सुरक्षा बलों से भिंग गए और आगजनी एवं पथराव कर व्यवस्था को चुनौती देने पर उत्तर आए। इन शहरों के अलावा दिल्ली स्थित शाही जामा मस्जिद से लेकर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, लुधियाना, और गंगाबाद, भद्रवाह, डोडा, किशतवाड़ आदि शहरों में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। कहीं-कहीं वे इतने उम्र थे कि या तो कफ्फूलगाना पड़ा या फिर धारा 144 लगानी पड़ी। इसके पहले 3 हित में है और न ही मुसलमानों के हित में। आखिर मुसलमान जुमे के दिन मस्जिदों से निकलकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा तो एक समय कश्मीर में होता था। क्या शेष देश का मुसलमान भी पथरबाज होने के ठप के साथ व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है मुसलमानों ने पहले ही दिन से नुपर और नवीन की टिप्पणियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। इसके बाद कई इस्लामी देशों ने भी विरोध जताया। इस पर केंद्र सरकार ने न केवल

अच्छी बात होगी? इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या इससे मुस्लिम समाज की छवि बेहतर होगी यदि मुसलमानों को किसी मुद्दे पर विरोध जताना है और शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी है तो यह काम मस्जिदों के जरिये और खासकर जमें की नमाज के बाद तो बिल्कुल प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे मुस्लिम समुदाय जानबूझकर या तो अलग-थलग रहना चाहता है या फिर उसके पास कोई दूरदृष्टि वाला नेतृत्व नहीं है। नुपुर शर्मा, नवीन जिदल या अन्य लोगों द्वारा पैंगांवर मोहम्मद साहब के बारे में की गई अंवाञ्छित टिप्पणियों की हिंदू

भा नहीं हाना चाहए। सामाजिक, राजनीतिक अथवा व्यवस्थागत मुद्दों की लड़ाई उचित मंच के माध्यम से सही तरीके से ही लड़ी जानी चाहिए। धार्मिक स्थलों का सहारा लेकर अपनी बात कहना और उस दौरान हिंसा करना संवैधानिक व्यवस्था को चुनावी देना है। किसी मुद्दे पर विरोध प्रकट करने के लिए जो ताकतें मुसलमानों को मर्सिदों से बाहर लाकर सड़क पर हिंसा करने को उकसाती हैं, उनसे मुस्लिम समाज को सावधान रहना होगा। उसे इस पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि उसकी रहनुमाई कैसे लोग कर रहे हैं? इसके पहले 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध के नाम पर भी मुस्लिम समाज की दिशानीता देखने को मिली थी। दिल्ली में सीएए विरोधी आंदोलन का अंत दंगों के साथ हुआ, लेकिन लगता है कि इसके बाद भी जरूरी सबक नहीं सीखे गए। पैंगंबर मोहम्मद साहब पर अवांछित टिप्पणी को लेकर औसत मुसलमानों की समाज के तमाम लोगों ने भा खुलकर आलोचना की है। बलिया, कानूनपर समेत देश के कई हिस्सों में इंटरनेट मीडिया पर अनाप-शनाप लिखने वालों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। मुस्लिम समाज किसी मसले पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाएगा, पुलिस को निशाना बनाएगा, सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा और मर्सिदों को आड़ लेकर अव्यवस्था फैलाएगा तो इससे देश-दुनिया को गलत संदेश तो जाएगा ही, जिन लोगों का साथ मिल रहा है, वे भी किनारा करना पसंद करेंगे। इस्लाम में जूत्थ पर सब्र को तरजीह दी गई है। 10 जून को देश के तमाम शहरों में जो हिंसा हुई, उसे लेकर मुस्लिम समाज को खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या वे सही रास्ते पर हैं मुसलमानों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर उनके ऐसे व्यवहार के बाद शेष देश को उनका साथ क्यों देना चाहिए।

A photograph showing a group of men in white shirts, likely political leaders, standing outdoors. In the foreground, an older man with glasses and a white shirt is looking towards the camera. Behind him, another man in a white shirt is speaking. The background shows greenery and other people.

रेहड़ी में न्यूज़ जा के जा व्यारु स्टर्टर्स को है, में ओप्रेटर रेहड़ी में न्यूज़ जा के

राजनीति अन्य पिछड़ा वर्ग पर आधारित है, इसीलिए भाजपा सहित सभी दल जातिगत जनगणना का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जनता को पता है कि जातीय जनगणना मात्र से उसे आरक्षण या सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि देश में 'अस्मिता' की राजनीति अर्थात् जातीय राजनीति की जमीन खिसक रही है और लोग धीरे-धीरे समावेशी राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें सभी का विकास निहित है। जातिगत जनगणना की कवायद आसान नहीं। उसके आंकड़ों को एकत्र कर विशेषित करना भी एक चुनौती है। मनमोहन सरकार द्वारा 2011 में जो सामाजिक-आर्थिक-परिवर्तिक

नगण्यना हुई, उसके आकड़ गिरात नहीं हो सके। अंतिम वित्तिगत जनगणना 1931 में हुई, जिसमें 4,147 जातियां चिह्नित की थीं, किंतु 2011 की जनगणना 46 लाख से अधिक जातियों/जातियों को दर्ज किया गया। खिर इतनी बढ़ातीरे कैसे संभव देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातियों समरूप वर्गीकरण संभव नहीं क्योंकि कोई जाति एक राज्य ओबीसी है, तो दूसरे राज्यों में पान्य वर्ग में है। बिहार में बनिया/योबीसी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य शा, दिल्ली में सामान्य वर्ग में है।

जातिगत जनगणना कराना न ता व्यावहारिक है, न ही प्रशासकीय रूप से संभव है। जातिगत जनगणना में नागरिक से केवल उसकी जाति या जाति-समूह पूछा जाएगा। उसे कोई दस्तावेज़ नहीं दिखाना पड़ेगा। बिहार में बड़ी संख्या में रोहिया मुस्लिमों का जमावड़ा है। संभव है वे स्वयं को न केवल जातिगत जनगणना में शामिल करा लें, बल्कि कटिहार, किशनगांज, अररिया और पूणिया अदि जिलों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्वयं को ओबीसी में शामिल कराएं। अनेक मुस्लिम जातियां जैसे कसब, चिक, डफली, धोबी, धुनियां, नट, नालबंद, पमारिया, भतिआर, मेहतर, लालबंगी, अंसारी, जलाहा, रंगरेज, कुंजरा, दर्जी आदि पहले से बिहार में 'ओबीसी' शामिल हैं और आरक्षण का लाभ ले रही हैं। चूंकि जातिगत जनगणना के आंकड़ विधिक दस्तावेज़ नहीं, इसलिए उसके द्वारा किसी को

ो कर्नाटक में ओबीसी तो आंध्र सामान्य वर्ग में है। केंद्र ने सर्वीच्य न्यायालय में जनगणना 2011 के तिवार अंकड़े सार्वजनिक न करने यही सब कारण बताए थे। जातिगत जनगणना कराना न तो विवाहारिक है, न ही प्रशासकीय वर्ग से संभव है। देश में राष्ट्रीय वर्ग पर जातियों का समरूप कार्यकरण संभव नहीं है, क्योंकि इस जाति एक राज्य में ओबीसी तो दूसरे राज्यों में सामान्य वर्ग है। बिहार में बनिया/वैश्य बीसी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में सामान्य वर्ग में है। कर्नाटक में ओबीसी तो आंध्र सामान्य वर्ग में है। केंद्र ने सर्वीच्य न्यायालय में जनगणना 2011 के तिवार अंकड़े सार्वजनिक न करने यही सब कारण बताए थे।

सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं जातिगत जनगणना, खिसक रहा

जातीय राजनीति की जमीन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का सर्वदलीय निर्णय लिया है। इसके पूर्व फरवरी 2019 और 2020 में बिहार विधानसभा जातिगत जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है। क्या बिहार के दल समझते हैं कि जनगणना से बेहतर सामाजिक न्याय मिलेगा? जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने से राजनीतिक दलों को यही तो पता चलेगा कि कौन सा जाति समूह कितने प्रतिशत है। चूंकि बिहार में राजद और जदयू की



रेहड़ी में न्यूज़ जा के जा व्यारु स्टर्टर्स को है, में ओप्रेटर रेहड़ी में न्यूज़ जा के

राजनीति अन्य पिछड़ा वर्ग पर आधारित है, इसीलिए भाजपा सहित सभी दल जातिगत जनगणना का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जनता को पता है कि जातीय जनगणना मात्र से उसे आरक्षण या सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि देश में 'अस्मिता' की राजनीति अर्थात् जातीय राजनीति की जमीन खिसक रही है और लोग धीरे-धीरे समावेशी राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें सभी का विकास निहित है। जातिगत जनगणना की कवायद आसान नहीं। उसके आंकड़ों को एकत्र कर विशेषित करना भी एक चुनौती है। मनमोहन सरकार द्वारा 2011 में जो सामाजिक-आर्थिक-परिवर्तिक



बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य...

नैनी/इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी एवं सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं के पास अपना भविष्य बनाने का सुनहरा मोका है। ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य बनाने का मोका नैनी इंडिस्ट्रियल इंस्टीट्यूट दे रहा है। यह जापि बिना अतिरिक्त समय गणना से तीनों बोर्ड के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर्ण प्रदेश के तकरीबन छोटीसाल लाख विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के साथ अच्छे करियर की भी चिंता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई में चलने वाले कोर्सेज फॉर्म स्टडी के रूप में सामने आए हैं। थीरे-थीरे यह रोजगार की गारंटी बनते हैं। इसके अलावा आईटीआई में एक लाख से अधिक विद्यार्थी की मांग है। इसके विपरीत हर साल मात्र तीस हजार प्रशिक्षित युवा मिल रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों में सैकड़ों पदों के लिए आईटीआई पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में डेरों संभाननाएं हैं ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि पंखरागत कोर्स के साथ युवा आईटीआई की ओर ध्यान देकर बेहतर कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा

पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह एक बेहतर विकल्प है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवत्तन दरूण स्वरजा से हुई खास बातचीत में उहने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पृष्ठ- गण सवाल

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र क्या है? इसके बारे में बताएं।

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो नैनी परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।



द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनसीबीटी-डीजीटी-नई दिल्ली, एनआईओएस - नई दिल्ली।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन से क्या लाभ है?

उत्तर- गर्तमान परिवृद्धि में पाठ्यक्रम आईटीआई द्वारा समय पर परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं?

उत्तर- कोा (कम्प्यूटर अपरेटर एण्ड प्रोग्रेमिंग आसिस्टेंट), फैटर, बेसिक कम्प्यूटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फायर प्रीवेशन एंड इंडिस्ट्रियल सेफ्टी, सिक्युरिटी सर्विस, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड मैटेनेंस इन कंप्यूटर एंड कॉम्प्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग इन्शियन, रोफेजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, योग असिस्टेंट, वैल्डग ट्रैकोलॉजी, सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकिंग इन्शियन, ट्रीवाइंग।

प्रश्न- आपके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में क्या अंतर है?

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ प्रमाणित है एवं श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इच्छी स्टार (सिस्टर) प्रैदिंग की गई है एवं एम.आई.एस.डिफेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र भी नियुक्त किया गया है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर इस प्रकार है- 0532-26958959, 9415608710, 9415608783, 9415608790, 7380468640, 6394370734।



सृष्टि सिंह मिसेज एशिया पेसिफिक नैनी आईटीसी के छात्रों को साथ।

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य



एसके गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई नैनी, नैनी आईटीसी के अनुदेशकों से बात करते हुए।



आरके दुबे प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई भद्रोही नैनी आईटीसी की वेबसाइट का विमोचन करते हुए।

कार्यालय प्रधानाचार्य नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

सीधे प्रवेश सुचना

नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तावित व्यक्तियोगी में अगस्त 2021 में प्रारम्भ होने वाले चार में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग एवं नैनी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया, फिटर, ऐसिक कल्याणिंग, आटा एन्टी ऑपोलोल, कायर फ्रीमेनाल एवं इण्डस्ट्रीयल सोफ्टवर, नियोरिटी सार्किल, कम्प्यूटर हार्डवेयर असेंबली एवं मेनटेनेंस, सार्टिफिकेट हृषक न्यूट्रिट एप्लीकेशन (सीएनीएलए), इलेक्ट्रिकल टेक्निकलिंग, रेफिजरेशन एन्ड प्रॉजेक्शन, योगा अशिस्टेंट, लैंडिंग टेक्नोलॉजी, सीटिंगनर्हॉल प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर टीकार ट्रेनिंग कोर्स के लिए न्युनतम शैक्षिक योग्यता लाईस्युल उल्लिखित है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया के लिए हमारी वेबसाइट www.nainiiti.com पर जाएँ Student's Zone → Online Form → Choose Course → Apply Now

यह आपने व्यवसाय कोर्स का चयन कर आपना प्रवेश सुनिश्चित करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवार कार्ड एवं 4 पासपोर्ट चाहज कोटीयाक के साथ प्रवेश कार्यालय में शामिल करें।

नोट:- प्रवेश प्राप्त करने की अनितम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए

visit us at : www.nainiiti.com

प्रवेश कार्यालय :- त्रिलोकपुरी प्लाजा टीसरी मॉडिल, एम.जी. मार्ग, चिकिता लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

फोन करें :- 0532-2695850, 9415608710, 6394370734, 7355448437, 6386474074, 6306080178, 9026359274